the efforts made by the industry to study the market; and

(b) if so, the broad out-lines of the steps taken in the direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) An Industry service Cell has been set up in the National Seeds Corporation to work out the requirements of seed processing equipment in the country and intimate them to the manufacturers in the country. The Cell will also maintain contacts with the manufacturers of various seed processing equipment in the country.

वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश में गेहूं तथा चावल का उत्पादन

4863. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश में गेहूं तथा चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) वर्ष 1970 में इस राज्य में इनका कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) अखिल भारतीय अंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1968–69 के दौरान मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 2007.5 हजार मीटरी टन तथा चावल का उत्पादन 3004.6 हजार मीटरी टन था ।

(ख) वर्ष 1969-70 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन के अखिल भारतीय तथा राज्यवार अंतिम अनुमान वर्तमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1970 में किसी समय, उपलब्ध होंगे ।

मध्यप्रदेश में गेहूं और चावल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र

4864. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी भूमि पर गेहूं और चावल की खेती होती है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में कितने एकड़ भूमि पर खेती नहीं की जाती है और सरकार द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार ऐसी कितनी एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के आधार पर, 1968–69 की अवधि में मध्य प्रदेश में गेहूं का क्षेत्र 3055.6 हजार हैक्टार तथा चावलों का क्षेत्र 4391.2 हजार हैक्टार था ।

(ख) 1959 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त अकृष्य भूमि सर्वेक्षण और भूमि सुधार समिति ने मध्य प्रदेश राज्य में सुधार के लिए 101 हैक्टार (250 एकड़) अथवा उससे अधिक के खंडों में 1.03 लाख हैक्टार भूमि का पता लगाया था । किन्तु समिति ने अनुभव किया कि इस क्षेत्र में से केवल 0.82 लाख हैक्टार भूमि ही लाभकारी लागत पर कृषि के अन्तर्गत लायी जा सकती है । अकृष्य भूमि के सर्वेक्षण और वर्गीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1968–69 के अन्त तक 101 हैक्टार से कम के खंडों में 9.38 लाख हैक्टार अकृष्य भूमि को कृषि के योग्य पाया गया था ।

Introduction of Dry Farming Scheme

4865. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the dry farming scheme to be introduced in the current year; and

(b) the areas in different States selected for the purpose of the operation of this scheme?